Prices of milk in,Delhi

1380. SHRI ISH DUTT YADAV: Witt the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a proposal is lying panding with Government to increase the prices of Milk in Delhi being implied through DMS and Mother Dairy; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) and (b) The price of milk supplied by the Mother Dairy is determined by the Mother Dairy itself. The price of milk supplied by the Delhi Milk Scheme is determined by the Government from time to time taking into account factors like the price of raw milk and other ingredients required for constitution of the liquid milk and ad-minittrative/overhead costs incurred by the Demi Milk Scheme.

दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार

1381. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० विजेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, दूध की खरीद में अनियमितताओं और इसकी आपूर्ति में अकुशलता के बारे में गत कुछ महीनों में अनेक शिकायतें की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शिकायतकर्ताओं में एक शिकायतकर्ता "दिल्ली दुग्ध योजना" में ही कार्यरत कर्मचारियों की यूनियन ही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त यूनियन द्वारा की गयी शिकायत का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी०लेंका) (क) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना में दूध की खरीद-फरोख्त/वितरण में अनियमितता बरतने, दूध के ठेके देने में पक्षपात करने, अधिकारी/कर्मचारी विशेष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें कभी-कभी दिल्ली दुग्ध योजना कर्मचारी संघों के नाम से भी की जाती हैं। शिकायतों की उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जांच-पड़ताल की जाती है जिनमें जहां कहीं आवश्यक हो, मामलों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजना भी शामिल है।

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना

1381. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन सरकार के पास विचारार्थ लम्बित है; और

(ग) क्या सरकार इन संयंत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने के लिए कतिपय शर्तें लगाने का विचार रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) यद्यपि विदेशी इक्विटी होल्डिंग वाली किसी कम्पनी से दूध के प्रसंस्करण तथा पैकिंग के लिए संयंत्र लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि ऐसी पांच कम्पनियों ने जुलाई 1991 के पश्चात्, जब से दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण को लाइसेंस से मुक्त किया गया था, दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण/मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के लिए सूचना ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।

(ग) और (घ) दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त किया गया है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शर्तें लगाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

Real Estate Business

1383. SHRI TINDIVANAM O. VENKATRAMAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of growth of Real Estate business at the cost of wet lands in rural as well as urban areas;

(b) whether Government propose to put a half to this menace since there can be no substitute for a cultivable land in Agriculture;

(c) whether it is a fact that there is growth of population but the cultivable agricultural land is fastly disappearing at the hands of Real Estate Agents;

(d) whether it is also a fact that the disappearance of cultivable land cannot be regained or fresh cultivable land could not be created; and

(e) the manner in which Government propose to tackle the problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA) : (a) to (c) The Government is aware of diversion of agricultural land for non-agricultural purposes including housing. Regulation of land use is the primary responsibility of the State Governments. Central Government has formulated National Land Use Policy Outline (NLPO) and recommended to the States for implementation ; this Policy outline envisaged restructuring of urban policy to ensure that highly productive land is not taken away for urban use.

(d) No, Sir.

(e) As stated in response to parts (a) to (c) above.

Support price of wheat

1384. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the support price fixed by Government for wheat is very meagre and the farmers are not willing to sell wheat on the price fixed by Government; and

(b) if so, whether Government propose to increase the minimum support price for wheat ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K..C. LENKA) : (a) and (b) The minimum support price of wheat for the current marketing season has been fixed at Rs. 250 per quintal which is higher by Rs. 25 per quintal as compared to the minimum support price fixed for the previous season. The minimum support price of wheat has been fixed on the basis of the recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), views of State Governments, concerned Central Ministries, etc. At present, there is no proposal to further increase the minimum support price of wheat. The Government has, however, decided that a bonus of Rs. 25 per quintal will.be paid to the farmers who sell wheat to food Corporation of India and its agencies procuring for the Central Pool during the period 1-4-92 to 31-5-92.

Delhi Milk Scheme

1385. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what is the production capacity of the Delhi Milk Scheme (DMS) in the month of April, 1992 ;

(b) whether Government have any plans to increase its present capacity ; and

(c) if so, the details in this regard?